

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10293/2024

सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 4 एफ-15, ओलिवर हाउस, न्यू पावरहाउस रोड, जोधपुर (राजस्थान) में है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल), कमरा नंबर 307, तीसरी मंजिल, विद्युत विनायक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302005, राज।
- मुख्य अभियंता, आरआरवीयूएनएल, कमरा नंबर 307, तीसरी मंजिल, विद्युत विनायक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302005, राज।
- उप मुख्य अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कमरा नंबर 307, तीसरी मंजिल, विद्युत विनायक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302005, राज या पांचवीं मंजिल, ड्रेमैक्स प्लाजा, सहकार मार्ग-302001
- एनआरसी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 9 वीं मील का पत्थर, कश्मीर रोड, वेरका, अमृतसर-143501 में है।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सुशील डागा के साथ श्री अनुराग कलावतिया, श्री चित्रांश माथुर, सुश्री पारुल सिंघल, श्री आशीष शर्मा और श्री आदित्य शर्मा
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री कार्तिक सेठ के साथ श्री दर्श पारीक, श्री चिरंजीव शर्मा, श्री राघव शर्मा, सुश्री श्रेया गिलहोत्रा और श्री केशव पाराशर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के लिए श्री समीर सोढी के साथ

		श्री पुनीत सिंघवी और श्री अजय सिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 5 के लिए
--	--	---

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन
आदेश

29/11/2024

- यह याचिका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (इसके बाद 'निगम' के रूप में संदर्भित) द्वारा मैसर्स एनआरसी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'प्रतिवादी संख्या 5' के रूप में संदर्भित) के पक्ष में जारी आशय पत्र (संक्षेप में 'एलओआई') दिनांक 10.06.2024 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और कन्वेयर बेल्ट के निर्माण और आपूर्ति में संलग्न है। निगम ने विभिन्न बिजली संयंत्रों के लिए कन्वेयर बेल्ट की खरीद हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (संक्षेप में 'एनआईटी') दिनांक 07.12.2023 जारी की। बोलीदाता के लिए योग्यता शर्तें एनआईटी के खंड 3 में थीं। याचिकाकर्ता ने भाग लिया और असफल रहा। याचिकाकर्ता ने संचार दिनांक 30.04.2024 के माध्यम से आपत्ति उठाई कि प्रतिवादी संख्या 5 के पास आवश्यक योग्यता नहीं थी। इस संचार को कानूनी नोटिस दिनांक 22.05.2024 का समर्थन प्राप्त था। निगम द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में एलओआई दिनांक 10.06.2024 जारी होने पर, वर्तमान याचिका दायर की गई है।
- 25.06.2024 को समन जारी करते समय, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को एलओआई दिनांक 10.06.2024 के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 5 को कार्य आदेश जारी करने से रोक दिया गया था।
- स्थगन निरस्तीकरण आवेदन की सुनवाई न होने से व्यथित होकर, मामले को रिट अपील में लिया गया। खंडपीठ ने 19.11.2024 को रिट का एक महीने के भीतर अंतिम निपटान करने का आदेश पारित किया।

5. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के पास राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (संक्षेप में '2012 का अधिनियम') के तहत अपील का सांविधिक उपचार होने पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण प्रक्रिया (संक्षेप में 'जीएचपी') के खंड-बी(बी) के मद्देनजर अपील विचारणीय नहीं है। दलील यह है कि एनटीपीसी ने आदेश दिनांक 07.08.2022 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को 10.08.2022 से 09.08.2023 की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंधित होने के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 5 के पास एनआईटी के खंड-3 के अनुसार आवश्यक योग्यता नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि निगम के अधिकारियों का कार्य दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और पक्षपात से भरा था और रिट याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिनमें बंसीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य जो 2024 एससीसी ऑनलाईन एससी 2700 में रिपोर्ट किया गया है; मिहान इंडिया लिमिटेड बनाम जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य जो 2022 एससीसी ऑनलाईन एससी 574 में रिपोर्ट किया गया है।
7. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 ने यह दर्शाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे कि वह एनटीपीसी का अनुमोदित विक्रेता था। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एनटीपीसी की सहायक कंपनी को बेल्ट की आपूर्ति की गई थी।
8. प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता 02.07.2020, 23.07.2020 और 27.07.2020 के खरीद आदेशों पर भरोसा करते हैं ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रतिवादी संख्या 5 एक अनुमोदित विक्रेता था, उसे खरीद आदेश प्राप्त हुए थे और उसने एनटीपीसी की सहायक कंपनी को आपूर्ति की थी।
9. आगे बढ़ने से पहले, एनआईटी के खंड 3(1) को पुनरुत्पादित करना प्रासंगिक होगा:

"बोलीदाता 2400 मिमी या उससे अधिक चौड़ाई और 1600 केएन/एम या उससे अधिक की तन्य शक्ति वाले "एफआर ग्रेड कन्वेयर बेल्ट" का निर्माता और आपूर्तिकर्ता होना चाहिए, और उसके पास "आईएस:1891 (भाग वी), आईएसओ 340, कैन./सीएसए/एम 422/एम 87 टाइप सी, डीआईएन 22131 (भाग-1) आईएस-15427" के अनुसार इन-हाउस परीक्षण सुविधा होनी चाहिए, जैसा लागू हो। बोलीदाता पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों में से किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान एनटीपीसी का अनुमोदित विक्रेता होना चाहिए और उसने बोली आमंत्रित किए जाने वाले महीने के अंतिम दिन से पिछले सात (07) वर्षों के दौरान किसी भी एनटीपीसी/सरकार/अर्ध-सरकारी/पीएसयू/बीएसई या एनएसई सूचीबद्ध कंपनी को उपर्युक्त ग्रेड बेल्ट की आपूर्ति की होनी चाहिए, और उसने निम्नलिखित में से कोई एक निष्पादित किया होना चाहिए:

तीन समान आदेश निष्पादित किए गए हों, जिनमें से प्रत्येक की लागत न्यूनतम 666 लाख रुपये हो।

या

दो समान आदेश निष्पादित किए गए हों, जिनमें से प्रत्येक की लागत न्यूनतम 832 लाख रुपये हो।

या

एक समान आदेश निष्पादित किया गया हो, जिसकी लागत न्यूनतम 1331 लाख रुपये हो।"

10. एनआईटी में उल्लिखित जीएचपी का प्रासंगिक भाग नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"खरीद प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण प्रक्रिया (अपील)

ए). अपील दायर करना:-

यदि कोई बोलीदाता या संभावित बोलीदाता खरीद इकाई के किसी भी निर्णय, कार्रवाई या चूक से व्यथित है, तो वह ऐसे निर्णय, कार्रवाई या चूक की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में अपील दायर कर सकता है, जिसमें वह विशिष्ट आधार या आधार स्पष्ट रूप से बताएगा जिन पर वह व्यथित महसूस करता है: बशर्ते कि किसी बोलीदाता को सफल घोषित किए जाने के बाद, अपील केवल उसी बोलीदाता द्वारा दायर की जा सकती है जिसने खरीद कार्यवाही में भाग लिया है: बशर्ते कि यदि कोई खरीद इकाई वित्तीय बोली खोलने से पहले तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है, तो वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उसी बोलीदाता द्वारा दायर की जा सकती है जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य पाई जाती है। पक्षों को सुनने के बाद, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील का निपटान करेगा और अपील दायर करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक आदेश पारित करेगा: यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटान करने में विफल रहता है या यदि बोलीदाता या संभावित बोलीदाता या खरीद इकाई प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, तो बोलीदाता या संभावित बोलीदाता या खरीद इकाई, जैसा भी मामला हो, बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को पंद्रह दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर कर सकता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, पक्षों को सुनने के बाद, अपील का निपटान करेगा और 30 दिनों की अवधि के भीतर एक आदेश पारित करेगा जो पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बी). कुछ मामलों में अपील नहीं होगी:-

ए. खरीद की आवश्यकता का निर्धारण;

बी. बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं की भागीदारी को सीमित करने वाले प्रावधान;

सी. बातचीत में प्रवेश करने या न करने का निर्णय;

डी. खरीद प्रक्रिया को रद्द करना;

ई. गोपनीयता के प्रावधानों की प्रयोज्यता।"

11. याचिका में उठाया गया मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 5 पिछले तीन वित्तीय वर्षों में एक अनुमोदित विक्रेता होने की आवश्यकता को पूरा कर रहा था और उसने एनटीपीसी या अन्य निर्दिष्ट संस्थाओं को कन्वेयर बेल्ट की आपूर्ति की थी।

12. स्थापित मामला यह है कि प्रतिवादी संख्या 5 को 10.08.2022 से 09.08.2023 तक प्रतिबंधित किया गया था और वह एनआईटी में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण के अनुसार, प्रतिबंधित होने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 5 वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक अधिकृत विक्रेता था, उसने एनटीपीसी की सहायक कंपनी को कम से कम तीन आपूर्तियां की थीं और इस तथ्य को एनटीपीसी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था। इस मुद्दे का निर्णय करने के लिए एनआईटी के खंड-3 की व्याख्या के अलावा, तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं।

13. यह दलील कि जीएचपी के खंड-बी(बी) के मद्देनजर अपील दायर नहीं की जा सकती, निराधार है। एनआईटी की भाषा स्पष्ट है कि 2012 के अधिनियम के प्रावधान निविदा प्रक्रिया पर लागू होते हैं। एनआईटी में जीएचपी के खंड-ए और बी 2012 के अधिनियम की धारा 38 और 40 के समतुल्य हैं और अधिनियम को इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था:

"पारदर्शिता, बोलीदाताओं के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दक्षता और अर्थव्यवस्था बढ़ाने और खरीद प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा की रक्षा करने के उद्देश्यों के साथ सार्वजनिक खरीद को विनियमित करना और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए।"

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 2012 के अधिनियम की धारा 2 के उप-खंड (xv) यानी 'खरीद प्रक्रिया' की परिभाषाओं पर यह तर्क देने के लिए भरोसा करना कि एलओआई जारी होने के बाद अपील दायर नहीं की जा सकती, कोई लाभ नहीं देता है। जीएचपी के खंड ए और बी बोलीदाता के एलओआई जारी होने के बाद अपील दायर करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। प्रथम और द्वितीय अपील का सांविधिक उपचार अधिनियम में और जीएचपी में भी प्रदान किया गया है। जीएचपी का खंड-ए व्यापक रूप से लिखा गया है और खरीद इकाई के किसी भी निर्णय, कार्रवाई या चूक से व्यथित बोलीदाता या संभावित बोलीदाता को अपील का उपचार प्रदान करता है। खंड-ए का पहला परंतुक स्थिति को स्पष्ट करता है कि बोलीदाता को सफल घोषित किए जाने के बाद भी अपील दायर की जा सकती है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि उस चरण में संभावित बोलीदाता को अपील दायर करने से बाहर रखा जाता है और केवल बोलीदाता ही अपील दायर कर सकता है। विवादों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जीएचपी ने निर्धारित किया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपील का निपटान करेगा और अपील दायर करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर एक आदेश पारित करेगा। पक्ष के असंतुष्ट होने की स्थिति में, दूसरी अपील का आगे का उपचार प्रदान किया गया है।

15. खंड-बी उन अपवादों को निर्धारित करता है जहां अपील नहीं होगी। वर्तमान मामले में प्रासंगिक खंड-बी(बी) है और यह प्रावधान करता है कि बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं की भागीदारी को सीमित करने वाले प्रावधानों के खिलाफ अपील नहीं होगी। यह अपवाद वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले में उठाई गई शिकायत प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में एलओआई जारी करने के संबंध में है, जबकि उसने एनआईटी के खंड-3 के अनुसार योग्यता पूरी नहीं की थी। जीएचपी के खंड-बी(बी) में उल्लिखित अपवाद से निपटने के लिए 'बोलीदाताओं की भागीदारी' से संबंधित 2012 के अधिनियम की धारा 6 प्रासंगिक होगी। धारा 6 खरीद एजेंसी द्वारा बोलीदाताओं की खरीद प्रक्रिया में भागीदारी को सीमित करने के उद्देश्य से किसी भी आवश्यकता को प्रतिबंधित करती है। वर्तमान मामला 2012 के अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के उल्लंघन का नहीं है, एनआईटी में भागीदारी को सीमित करने वाली कोई शर्त चुनौती के

अधीन नहीं है। खंड बी(बी) में अपवाद तब लागू नहीं होगा जब चुनौती प्रतिवादी संख्या 5 को आवंटित एलओआई को आवश्यक योग्यता न रखने के आधार पर दी गई हो।

16. निष्कर्ष निकालने से पहले, इस दलील से निपटना आवश्यक होगा कि निगम के अधिकारियों का कार्य मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और पक्षपात के लिए किया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि रिट याचिका में निराधार कथन करने के अलावा, निगम के किसी भी अधिकारी के खिलाफ दुर्भावना और पक्षपात के कोई विशिष्ट वादपत्र नहीं हैं। दूसरा पहलू यह है कि निगम के किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत क्षमता में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

17. निगम द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को एलओआई जारी करना, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता का असफल होना, अपने आप में निर्णय को मनमाना या दुर्भावना के इरादे से किया गया नहीं बना सकता है।

18. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि निगम के अधिकारियों की ओर से दुर्भावनापूर्ण या मनमानी कार्रवाई का कोई मामला नहीं बनता है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के बंसीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) और मिहान इंडिया लिमिटेड बनाम जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य (उपरोक्त) के निर्णयों पर भरोसा करना कोई मदद नहीं करता है।

19. याचिकाकर्ता को अपील के उपचार के लिए निर्देशित करते हुए रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन), न्यायमूर्ति

मोनिका / चंदन / 375

क्या रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

